

डा. (श्रीमती) नाजमा हेफतुल्ला : यह बड़े अफसोस की बात है कि महिला बिल ...(व्यवधान)...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, there is an intriguing silence on the part of the Government and the Prime Minister. *(Interruptions).*

श्री संजय निरुपम : मैं आप लोगों की सपोर्ट में खड़ा हूँ। लेकिन क्वेश्चन आवर के बाद अगर इस विषय पर बातचीत की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।(व्यवधान)....

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Let the Prime Minister say something. *(Interruptions).*

श्री संजय निरुपम : मेरे ख्याल से प्रश्न काल के बाद जीरो आवर में इस पर बात हो तो ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम प्रश्न काल को इस तरह बाधित न किया जाए।

डा० (श्रीमती नाजमा हेफतुल्ला) : महिलाओं के लिए वहां भी लोगों को खड़े होना चाहिए।(व्यवधान)....

श्री संजय निरुपम : हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग इसके अगेस्ट नहीं हैं।(व्यवधान)....

MR. CHAIRMAN: The Prime Minister has agreed.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति जी, सरकार महिलाओं के आरक्षण विधेयक को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आश करते हैं कि वह बिल सर्वसम्मति से पास होगा। उस विधेयक को प्रस्तुत करने का फैसला कर लिया गया था। लेकिन एक दल के कुछ सदस्यों ने कहा कि उसके कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार होना चाहिए। सर्वसम्मति बनाने के लिए यह तय हुआ कि एक सर्वदलीय बैठक फिर से आयोजित की जाए और उसमें अगर संभव हो तो सब की राय से विधेयक को पेश करने का फैसला किया जाए। वह बैठक आयोजित होने जा रही है। उसमें सर्वसम्मति बनाने का प्रयास होगा। मैं आश करता हूँ कि सर्वसम्मति बनेगी। लेकिन, जहां तक, हमारा प्रश्न है और मैं देख रहा हूँ कि अन्य सदस्यों की भी जहां तक राय है, वह राय यह बन रही है कि अगर सहमति न ही हुई तो भी विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए और हम ऐसा ही करने जा रहे हैं।

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति महोदय, केवल विचार के लिए नहीं। हम यह चाहते हैं कि विचार करने के साथ साथ इसको पारित कराने के लिए आप लायें इसमें आपका भी कमिटमेंट है।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Piling up of Steel at SAIL

*281 **SHRI SANJAY NIRUPAM:** Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) Whether a large quantity of steel is piling up at SAIL for the last few months;

(b) if so, the quantity lying at each plant/stockyard; and

(c) the steps being taken by Government to ensure that these stocks of steel are delivered to the steel users at the earliest?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) During the first three months of the current financial year, stocks at plants and stockyards system of Steel Authority of India Limited (SAIL) have been brought down. The total quantity of Saleable Steel (Mild Steel), lying in the four Integrated Steel Plants and the Stockyards, as on 01/07/1998, was approximately 1.14 million tonnes as against approximately 1.23 million tonnes (provisional) on 01/04/1998.

(c) Some of the steps being taken by SAIL to increase sales and reduce stocks, inter-alia, include fine-tuning the product-mix in terms of market requirement; entering into MOUs with customers for regular supplies during the year; adopting market driven pricing strategies; entering into supply arrangements through participation in tenders/negotiations with various customers including projects, Government Departments, PSUs, Railways, etc.; increasing the despatch directly to customers etc.

श्री संजय निरुपम : सर, स्टील की इनवेस्टमेंट्री का जो प्रश्न है वह बहुत पुराना है और यह बहुत गंभीर प्रश्न है। पिछले तीन-चार सालों से लगातार स्टील के अलग अलग जो एन्टीग्रेटेड प्लांट है, जैसे बोकारो हैं या भिलाई हैं, इन प्लांटों में स्टील का स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन डेढ़ मिलियन या पौने दो मिलियन तक यह पहुंच गया है और इसी के आधार पर मैंने यह सवाल किया था। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह एक अच्छी खुशखबरी देकर दिया गया जवाब है कि पिछले तीन महीनों में इन्वेन्ट्री कम हुई। अभी तक ऐसी खबर थी कि सेल की इनवेन्ट्री बढ़ रही है और सेल का प्रॉफिट घटता चला जा रहा है और स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए स्टॉक क्लियरेंस के नाम पर बहुत सारा स्टील रिबेट रि डिस्काउंट पर दिया जा रहा है और बहुत हद तक ऐसा किया जा रहा है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट के नाम पर एक हजार करोड़ रुपए का स्टील मॉर्ट में फेंक दिया गया है। वगैर किसी सिक्यूरिटी के क्रेडिट पर तकरीबन 700 से एक हजार करोड़ के बीच का स्टील मार्केट में यो ही फेंक दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि वगैर सिक्यूरिटी के, वगैर प्रॉपर सिक्यूरिटी के जो स्टीज मार्केट में दिया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है, यह क्या अच्छी बात है और जो अनसिक्युअर क्रेडिट है जो एक हजार करोड़ के आसपास है तो उस क्रेडिट को वापस लेने का क्या प्रावधान है? स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेरा यह है कि आखिर किस रेट पर स्टील बेचा जा रहा है? क्या वह जो मार्केट में स्टील का रेट है उससे कितने कम परसेंट पर बेचा जा रहा है? मैं मंत्री महोदय से विशेषतौर से यह जानना चाहता हूँ कि किस रेट पर स्टील बेचा जा रहा है और कितना समझौता इसमें किया जा रहा है, कितना कम्प्रोमाइज किया जा रहा है?

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, in reply to the hon. Member's question, I would say that there is credit to the extent of Rs. 800 crores. The method of this is that while extending unsecured credit, there is an internal mechanism for assessing the credit-worthiness of parties, however, there is no assessment of credit-worthiness of parties carried out through an outside agency.

श्री संजय निरुपम : मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी कम्पनीज हैं जिनको अनसिक्युर्ड क्रेडिट के आधार पर स्टील दिया गया है? मेरे पहले सप्लीमेंटरी का मुद्दा यही है

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, steel is being sold at market rates. There is a Committee of Directors in the Steel Authority of India Limited which, on a monthly basis, decides what the market rate has to be. Sir, the SAIL which is the major steel manufacturer has also got competition from other parties. So we have the Committee of Directors of the Steel Authority of India Limited and this Committee consists of Commercial Director, Finance Director and Chairmen and Managing Directors of the four integrated steel plants, namely, Rourkela, Bhilai, Bokaro and Durgapur.

श्री संजय निरुपम : मेरे इस सवाल का जवाब तो नहीं आया लेकिन मैं दूसरा सप्लीमेंटरी पूछता हूँ। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : यह तो तीसरा होगा (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : नहीं नहीं, मैंने दूसरा अभी नहीं पूछा है। जितनी इनवेंटरी बढ़ती जाती है लॉस उतना बढ़ता चला जाता है और प्रॉफिट कम होता चला जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि जब स्टील सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा था, उस समय सेल का प्रॉफिट 1991-92 में 367 करोड़ था। उसके बाद जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होता है 1995-96 में यह प्रॉफिट 1319 करोड़ हो जाता है। उसके बाद 1996-97 में एकदम 50 परसेंट प्रॉफिट हो जाता है और यह फिगर है 588 करोड़ इसके एक साल बाद 1997-98 में प्रॉफिट 116 करोड़ रह जाता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सेल का जो प्रॉफिट लगातार गिरता चला रहा है, क्या इस ओर उनका ध्यान है? सिर्फ स्टॉक क्लियरेंस या इनवेंटरी कम कर देने से बात नहीं बनने वाली है। मेरा जो पहले सप्लीमेंटरी में शक था वह यह है कि लोअर प्राइस पर अनसेसरी डिस्काउंट पर, अनसिक्युर्ड क्रेडिट पर स्टील को मार्केट में फेंका जा रहा है, इससे लगातार सेल का प्रॉफिट घटता जा रहा है। मुझे डर है कि एक ही साल में सेल लॉस में जा सकता है।

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, as I mentioned earlier, I am repeating for the hon. Member that we have a Committee Of Directors which, on a monthly basis, processes the price of Regarding reasons for the pile-up steel in the stockyards of SAIL as well as the four integrated steel

plants, there has been an improvement in the situation because on the 1st of April, this year, we had a stock of 1.23 million tonnes of saleable steel materials, but on the 1st of July, that is, on the 1st of this month, it has come down to 1.14 million tonnes, which is less than what it was on the 1st of April. The reasons for this...

श्री संजय निरुपम : यह जवाब हमें मिल चुका है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। (व्यवधान)

SHRI NAVEEN PATNAIK: I would request the hon. Member to repeat his question

श्री संजय निरुपम : मेरा कहना यह है कि लगातार प्रोफिट गिरता जा रहा है, इसका क्या कारण है ? क्या इसकी इन्व्वायरी सेट-अप की जा सकती है ? लगातार जो प्रोफिट सेल का घटता जा रहा है, क्या इस ओर मंत्री महोदय ने गम्भीरता से ध्यान दिया है, छानबीन या इन्व्वायरी की जा रही है ?

SHRI NAVEEN PATNAIK: I again repeat that we, on a monthly basis, review the sales. So far as enquiry is concerned, if an enquiry is required, of course, we shall look into the matter.

MR CHAIRMAN: The Minister has not properly answered the question. Probably he does not have the information.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Through you, Sir, I would like to put this question to the hon. Minister. He knows very well that the economy of any country depends upon core sectors. And steel is the major sector. Steel is being accumulated in steel plants, whether they are public or private. I would like to know what the Minister plans to do when MNCs from all over the world are dumping steel in the country. What are his plans to save this industry? This Government is talking about saving the Indian industry whereas what we are seeing is that steel production is going down and the stock is going up. There has been a reduction of stock of 90,000 tonnes only in one steel plant. My friend has already mentioned under what circumstances that has happened. Is it going to strengthen

the core sector, the steel industry? This is what I would like to know from the hon. Minister.

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, the Ministry of Steel has made it clear to SAIL that its performance has to improve in the coming months. We have asked them to take the following actions in particular; prepare a time-bound action plan for turn-around of Rourkela and Durgapur steel plants, which will be closely monitored by the Ministry; undertake comprehensive cost-reduction exercises for improvements in techno-economic implementation; undertake Voluntary Retirement Scheme and shed non-essential and non-core activities, etc.; devise more aggressive marketing strategies, both for domestic sales as well as for exports; target new areas of customers in order to attain a larger market share, and, improve the quality of their products so as to compete with other producers in the private sector.

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति महोदय, जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि स्टीज इंडस्ट्री ने पहले 1319 करोड़ रुपये तक का प्रॉफिट अर्जित किया था, लेकिन अब धीरे-धीरे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है। उसके कई कारण हैं। उसमें से एक एक्सपेंशन है। उसी से संबंधित मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो एक्सपेंशन हो रहे हैं स्टील प्लांट्स के, आपके पहले के प्रोडक्शन के आधार पर जितना सेल होता था उतना भी आप सेल, नहीं कर पाए। तब एक्सपेंशन में जो आपने 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किया है और वह अब लगभग पूरा हो चुका है, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा क्या आप उसको भी मार्केट में बेच पायेंगे ? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इंपोर्टेड जो स्टील हिन्दुस्तान में डंप किया गया है कि मल्टी नेशनल कंपनीज के माध्यम से तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बारे में क्या सरकार ने विचार किया है ?

SHRI NAVEEN PATNAIK: Sir, according to the recent Budget, there has been a price hike in the import of steel products. With the hike in the import duty, it is more expensive now to import steel. Therefore, that works...

श्री रामदास अग्रवाल : सर, मैंने तो यह पूछा था कि एक्सपेंशन के बाद सेल की क्या स्थिति बनेगी ?

MR. CHAIRMAN: Please. This is a very serious question. A number of interventions may be required. The Minister is not well-prepared. I may suggest that we should have a Half-an-Hour Discussion, when both the Minister and the Members come well-prepared. Somebody has to give notice and we shall decide.

Rate of Interest on the Corpus of Family Pension

*282 SHRI CO. POULOSE:

SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Standing Labour Committee has recommended enhancement of rate of interest on the corpus of family pension;

(b) if so, the details of the recommendations; and

(c) the steps taken by Government on these recommendations?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The Standing Labour Committee (SLC) of the Indian labour Conference had recommended that the Pension fund and the Employees Deposited-Linked Insurance Fund deposited in the Public Account should receive interest of not less than 12.5 percent as compared to the present return of 8.5 percent. The matter has been considered in consultation with the Ministry of finance. However, it has not been found possible to accept the proposal.

SHRI CO. POULOSE: Sir, my first supplementry is this: The Employees' Pension Scheme was made effective from 1995. The amount of Family Pension Fund was credited to the Employees' Pension Fund from the same date. The Government has not allowed interest rate

The question was actually asked on the floor of the house by Shri CO. Poulouse.

as recommended by the Standing Labour Committee. This amount is huge. It is more than ten thousand crores of rupees. Will the Minister please disclose the amount that the Pension Fund lost by a higher interest rate not being granted, as recommended by the Standing Labour Committee from the date of merging of this Fund with the Employees' Pension Fund?

डा० सत्यानारायण जटिया : माननीय सभापति जी, यह प्रश्न वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं किंतु पेंशन के संदर्भ में जो नीतिगत मामला हैं, उस बारे में प्रश्नकर्ता जानते-होंगे कि सन् 1971 से यह पेंशन स्कीम प्रारंभ हुई। इस पेंशन स्कीम में 1.16 परसेंट के हिसाब से केंद्रीब्यूशन होना था और यह कामगार, प्रबंधन और सरकार का ट्राइपाट्रडिट केंद्रीब्यूशन हुआ था। इस प्रकार इस स्कीम का प्रारंभ हुआ और उस वक्त इस पेंशन स्कीम का लाभ काम करते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने के उपरांत मिलता था। बाद में इस पेंशन स्कीम में संशोधन होता गया। यह भी पूछा गया कि इस पेंशन स्कीम के कारण एकमुलेशन हो गया है और वह राशि बहुत बढ़ गयी है इसलिए इस बढ़ी हुई राशि पर इंटररेस्ट रेट बढ़ा दिया जाना चाहिए जिससे कि उसका दायरा बढ़ सके।

सभापति जी, निश्चित रूप से प्रश्नकर्ता जानते होंगे कि यह जो स्कीम है, इस में सरकार को 1.16 परसेंट केंद्रीब्यूशन आता है। बाद के समय में इस कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी में एम्प्लायर्स का शेयर 8.5 परसेंट इस पेंशन स्कीम के केंद्रीब्यूशन में आता है। सभापति जी, जब यह नई पेंशन स्कीम बन रही थी तो उस पेंशन स्कीम में सभी ट्रेड यूनियंस का आग्रह था कि 1.16 परसेंट जो सरकार की ओर से केंद्रीब्यूशन जा रहा है, इस पर भी रेट ऑफ इंटररेट बढ़ाया जाय और चूंकि इस पेंशन स्कीम से सन् 1971 से लागू होने के बाद 1.16 परसेंट सरकार का पैसा उस में जाता है और जो सरकार का केंद्रीब्यूशन है उसी पर क्योंकि 8.5 परसेंट इंटररेस्ट मिल रहा है अब इस पर भी यह अपेक्षा की जा रही है कि 12 परसेंट से अधिक इंटररेट मिले। इस प्रश्न पर वित्त मंत्रालय में साथ चर्चा और विचार-विमर्श किया जा रहा है, किंतु उन का यह कहना है कि अभी तक इस बारे में कोई स्वीकारोक्ति नहीं मिली है, इसी कारण यह नहीं हुआ है।

सभापति जी, चूंकि आई० एल० सी० में भी यह इस प्रकार से मंजूर हुआ था और श्रम मंत्रालय ने इसे